

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
अंधेरी (पूर्व), मुंबई।

ANDHERI (EAST), MUMBAI.

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की 66वीं बैठक का एजेंडा
AGENDA FOR THE 66th MEETING OF THE SEEPZ
SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

स्थान: वीबेक्स एप्लिकेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

VENUE: Through video conferencing on Webex application.

दिनांक: 27.03.2024

DATE : 27.03.2024

समय : अपराह्न 3.30 बजे

TIME : 3.30 P.M

INDEX

Agenda Item No.	Subject	Page No.
<u>Action Taken Report of 65th Authority Meeting</u> <u>Dated 07.02.2024</u>		17
<u>Finance (Accounts & Procurement) Division</u>		
<u>Agenda Item No. 01</u>	सीपज़ एसईज़ेड का- वित्त वर्ष 25-2024 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव Proposal for approval of Annual Financial Statements for F.Y. 2024-25 of SEEPZ-SEZ	28
<u>Agenda Item No. 02</u>	अग्रदाय के माध्यम से किया गया मासिक विवरण व्यय। Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.	39
<u>Agenda Item No. 03</u>	प्राधिकरण मामलों से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक देने की प्रथा पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव। Proposal to revisit the practice of awarding remuneration given to Govt employees for their work related to Authority Matters.	45
<u>Agenda Item No. 04</u>	वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजना Mega CFC बजट प्रावधानों के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव। Proposal for up-dation of ongoing project Mega CFC Budget provisions for the year 2024-25.	48
<u>Agenda Item No. 05</u>	वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजना नेस्ट-02 बजट प्रावधानों के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव। Proposal for up-dation of ongoing project NEST-02 Budget provisions for the year 2024-25.	50
<u>Agenda Item No. 06</u>	वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजना नेस्ट-01 बजट प्रावधानों के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव। Proposal for up-dation of ongoing project NEST-01 Budget provisions for the year 2024-25.	52
<u>Estate Division</u>		
<u>A. Works</u>		
<u>Agenda Item No. 07</u>	मेगा सीएफसी के ग्राउंड से लेकर 5वें तल तक को जीजेईपीसी को सौंपने का प्रस्ताव। Proposal for handing over of Ground	56

	to 5 th floor of mega CFC to GJEPC.	
<u>Facility Management Division</u>		
<u>Agenda Item No. 08</u>	सीपज़-सेज़ में व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना। Setting up an OHC (Occupational Health Clinic) in SEEPZ SEZ.	60

अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 65th AUTHORITY MEETING HELD ON 07.02.2024 IN HYBRID MODE, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़	सदस्य/सचिव	1. Shri C.P.S Chauhan, JDC, SEEPZ SEZ	Member/Secretary
2. श्री अभय दोशी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड	सदस्य	2. Shri Abhay Doshi, MD, M/s. Fine Line Circuits Ltd.	Member
3 श्री आदिल कोतवाल, अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेसर्स क्रिएशन्स ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य	3. Shri Adil Kotwal, Chairman/CEO M/s. Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd.	Member
4. श्री हिमांशु धर पांडे, विदेश व्यापार उप महानिदेशक	सदस्य	4 Shri Himanshu Dhar Pandey, Dy. Directorate General of Foreign Trade	Member
5. डॉ. प्रसाद वरवंटकर, उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़	संपदा अधिकारी	5 Dr.Prasad Varwantkar, DDC, SEEPZ-SEZ	Estate Officer

संपदा संबंधी मुद्दों के लिए विशेष आमंत्रण:-

Special Invites for Estate related Issues :-

<p>- श्री मेहुल शाह, मेसर्स स्टार ब्रिलियन प्राइवेट लिमिटेड, कार्यसूची मद सं .10 के लिए।</p> <p>श्री प्रसाद वरवंटकर, उप विकास आयुक्त/संपदा अधिकारी, श्रीमती ब्रिजित जो, विकास आयुक्त की कार्यपालक सहायक, श्री हनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त, (सुरक्षा/आईटी), श्रीमती रेखा नायर, सहायक विकास आयुक्त, (ई एंड आर/कानूनी), श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री राजेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक भी बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए उपस्थित हुए। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद बैठक की एजेंडे पर विचार किया गया।</p>	<p>- Shri Mehul Shah, M/s. Star Brilliant Pvt. Ltd. for Agenda item no. 10.</p> <p>Shri Prasad Varwantkar, DDC/ Estate Officer, Smt. Bridget Joe, EA to DC, Shri Hanish Rathi, ADC (Security/IT), Smt. Rekha Nair, ADC (E&R/Legal), Shri Ravindra Kumar Assistant and Shri Rajesh Kumar, UDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.</p> <p>The Chairperson welcomed all the members present and thereafter agenda of the meeting was taken up.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Handwritten signature)

<p>कार्यसूची मद सं .1:- दिनांक 06.12.2023 को आयोजित 64वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।</p>	<p>Agenda Item No. 1:- Confirmation of the Minutes of the 64th Authority meeting held on 06.12.2023.</p>
<p>निर्णय: विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से दिनांक 06.12.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की और निर्देशित किया- :</p> <p>(1) संबंधित उप शीर्षकों के तहत विस्तृत व्यय-प्रस्तुत करने के लिए।</p> <p>(2) मौजूदा जनशक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से 02 पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्त करना। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय ने सीए अनुभाग की जांच निरीक्षण करने और रिपोर्ट/करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया।</p> <p>(3) वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी यानी मेसर्स अवध बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट (आई) लिमिटेड के माध्यम से या लघु निविदा के माध्यम से सीपज़ की आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करें।</p> <p>(4) संपदा अधिकारी को एएफआईएच डॉक्टरों की सुविधा के साथ एक पूर्ण विकसित स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना पर एक विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on 06.12.2023 with consensus and directed to:-</p> <p>a. Submit the detailed expenditure under the respective sub-heads.</p> <p>b. Engage full time 2 nos. of Chartered Accountant through existing manpower Service provider. Further, Chairman directed to form a committee to examine/inspect CA section and submit the report.</p> <p>c. Hire a consultant through outsourcing agency on boarded at present i.e. M/s Avadh Business Services (I) Pvt Ltd or through short tender for re-development of Residential colony of SEEPZ.</p> <p>d. The Estate Officer to chalk out a detailed plan on establishment of a full pledged health centre along with facility of AFIH doctors.</p>
<p>कार्यसूची मद सं .1- क:- सीपज़सेज़ प्राधिकरण के - में मासिक अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण व्यय का विवरण, व्यय का प्रतिशत एवं शेष का लेखाजोखा प्रस्तुत करना।-</p> <p>सीपज़ सेज़ प्राधिकरण ने वित्त वर्ष-2023-24 के लिए 313.90 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय विवरणी को स्वीकृति दी थी। बजटीय व्यय का भुगतान संबंधित बजटीय मद से किया जाता है। दिनांक 01-04-2023 से 03.02.2024 तक बजट के उपयोग का विवरण सीपज़सेज़ प्राधिकरण को - प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक बजट मद के अनुसार संक्षिप्त बजट व्यय भी प्रस्तुत किया गया था।</p>	<p>Agenda Item No. 1A:- Submission of Monthly expenditure accounts percentage of expenditure and balance in the approved annual financial statement of the SEZ Authority.</p> <p>The SEEPZ SEZ Authority had approved an Annual Financial Statement of Rs.313.90 Cr. for the FY 2023-24. The budgeted expenditures are paid from respective budgeted head. The details of utilization of budget from 01-04-2023 to 03.02.2024 are submitted to SEEPZ SEZ Authority. The summarized budgeted expenditure</p>

	as per each budgeted head was also submitted.
<p>निर्णय: विचारविमर्श के बाद, समिति ने 01-04-2023 से 03.02.2024 तक बजट के उपयोग का विवरण नोट किया और आगे किए गए व्यय की बेहतर तुलना के लिए उन परियोजनाओं का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके लिए किए गए प्रावधानों की तुलना में बेहतर प्रावधान किए गए थे।</p>	<p>Decision: After Deliberation, the Committee noted the details of utilization of budget from 01-04-2023 to 03.02.2024 and further directed to submit individual details of the projects for which the provisions were made for better comparison of the expenditure done vis-à-vis provisions made.</p>
<p>कार्यसूची मद सं. 2:- कार्य की तत्काल प्रकृति के लिए तत्काल उपयोग के लिए 30,000/- रुपये की अग्रदाय राशि अग्रिम नकद बढ़ाने/का प्रस्ताव, जिसे फिर से 1,00,000/- रुपये पर वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>संपदा अधिकारी को दी गई अग्रदाय राशि अग्रिम / नकद रोजमर्रा के काम के भुगतान के लिए अपर्याप्त है। चूंकि 30,000/- रुपये की सीमा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह प्रस्तावित है कि अग्रदाय खाते की सीमा को 1,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>Agenda Item No. 2:- Proposal for increase Imprest/advance cash of Rs. 30,000/- for immediate usage for urgent nature of work to Rs. 1,00,000/-.</p> <p>Imprest/Advance cash granted to the Estate Officer is insufficient to disposal of Payment of day to day work. As the limit of Rs. 30,000/- is not sufficient to meet the day to day requirements, it is proposed that the limit of Imprest Account may be enhanced to Rs. 1,00,000/-</p>
<p>निर्णय: विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के लिए तत्काल उपयोग के लिए 1,00,000/- रुपये की अग्रिम नकद राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्राधिकरण ने अग्रदाय निधि के माध्यम से किए गए व्यय का मासिक विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Authority approved the proposal for increase of Imprest/advance cash of Rs. 1,00,000/- for immediate usage for urgent nature of work. The Authority directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority in its meetings.</p>

8/3/23

कार्यसूची मद सं. 3:- प्राधिकरण निधि, 2023-24 से मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को 10,41,662/- रुपये का भुगतान किया गया।

आरपीएओ से धनराशि प्राप्त होने में देरी के कारण, प्रशासन अनुभाग ने सीपज़ सेज़ प्राधिकरण से- 10,41,662/- रुपये का भुगतान करने (जीएसटी सहित) का अनुरोध किया है और एक बार प्रशासन अनुभाग में बजट उपलब्ध होने पर उतनी ही राशि प्राधिकरण को वापस कर दी जाएगी। तदनुसार, अक्टूबर और नवंबर, 2023 के महीने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को 10,41,662/- रुपये का भुगतान जारी (जीएसटी सहित) किया गया है।

निर्णय: विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण निधि, 2023-24 से 10,41,662/- रुपये के भुगतान को मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि भारत सरकार के बजट से रिफंड के बाद उसे जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

Agenda Item No. 3:- Payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24.

Due to delay in receipt of funds from RPAO, the Administration Section under DC office has requested to make the payment of Rs. 10,41,662/- (inclusive of GST) from SEEPZ-SEZ Authority accounts and once the budget is available in Admin Section the same amount will be refunded back to the Authority. Accordingly, the payment amounting to Rs. 10,41,662/- (inclusive of GST) has been released to M/s. GA Digital Web Word Pvt. Ltd. towards salaries of outsourced employees for the month of October and November, 2023.

Decision: After deliberation, the Authority approved the payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24 and directed that after refund from the Government of India budget the same should be placed before the Authority for information.

[Handwritten signature]

कार्यसूची मद सं .4:- "स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियो का प्रस्ताव। (

इस प्राधिकरण ने, सभी यूनिट धारकों के साथ मिलकर दिनांक 19.12.2023 से 25.01.2024 तक सीप्लसेज़ में - बीएफसी बिल्डिंग में "स्वस्थ नारी विकसित भारत" विषय के तहत महिला स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिससे सीप्ल की 10000 से अधिक महिला कर्मचारी लाभान्वित हुईं। विभिन्न मंचों पर परिणामों को पेशेवर तरीके से प्रदर्शित करने और इस आयोजन की स्मारिका के रूप में बेहतर गुणवत्ता के वीडियो का बनना आवश्यक है। मेसर्स ग्रीन सिग्नल एंटरटेनमेंट के पिछले अनुभव के आधार पर, जिन्होंने इन परियोजनाओं के उद्घाटन पर माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुति के लिए मेगा सीएफसी और एनईएसटी 1 परियोजना के वीडियो बनाए थे, उनसे इन वीडियो को बनाने के लिए 4,00,000 रुपये के 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियो के लिए कोटेशन (मांगा गया था।

निर्णय:- विचारविमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स ग्रीन सिग्नल एंटरटेनमेंट से "स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियो की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई (क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता और व्यावसायिकता साबित कर दी थी। हाल ही में उन्होंने मेगा सीएफसी और एनईएसटी 01 के उद्घाटन के लिए बहुत ही कम समय में गुणवत्तापूर्ण वीडियो उपलब्ध कराया था।

कार्यसूची मद सं .5:- मेगा सीएफसी में टेंडर बीओक्यू से परे अतिरिक्त कार्यों और मदों के लिए स्वीकृति।

निर्माण और आंतरिक कार्यों के दौरान, यह देखा गया कि कुछ कार्य BoQ का हिस्सा नहीं थे या कार्य को पूरा करने के लिए BoQ की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। चूंकि काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है, इसलिए ठेकेदारों को काम पूरा करने और आरएफपीसंविदा करार के नियमों /

Agenda Item No. 4:- Proposal for 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikasit Bharat".

This Authority, in association with all unit holders, had organized a women health check up and health awareness programme under theme "Swasth Nari Vikasit Bharat" at BFC Building in SEEPZ SEZ from 19.12.2023 to 25.01.2024 wherein over 10000 women employees at SEEPZ were benefited. To showcase the outcome at various forums in a professional manner and as a souvenir of this event, it is necessary to have videos of better quality. Based on the previous experience of M/s Green Signal Entertainment, who made the videos of Mega CFC and NEST 1 project for presentation before Hon'ble Prime Minister at the inauguration of these projects, quotation was asked for 3 videos (One 5 minute video + 2 short duration videos) of Rs 4,00,000 for making these videos.

Decision: - After deliberation, the Committee approved the proposal for procurement of 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikasit Bharat" from M/s Green Signal Entertainment as they had proved their competence and professionalism by providing quality video in recent past at a very short notice for Mega CFC and NEST 01 inauguration.

Agenda Item No. 5:- Approval for additional works and items beyond the Tender BoQ at Mega CFC.

During the Construction and Interior works, it was observed that some works were not part of the BoQ or the BoQ quantities were not sufficient to complete the works. Since the works are to be completed in a time bound manner, the Contractors were asked to carry out the works and submit the

2/43

और शर्तों के अनुसार मामले की जांच और निर्णय के लिए निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष विवरणमात्रा प्रस्तुत / करने के लिए कहा गया था। मेगा सीएफसी के मामले में टीईसी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को पुष्टि के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

निर्णय:- विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने मेगा सीएफसी परियोजना के लिए अतिरिक्त कार्य और या / अतिरिक्त मात्रा के संबंध में टीईसी द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की। इसके अलावा, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीईसी को ऐसी प्रकृति का निर्णय लेने का अधिकार है और इन मामलों को केवल जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।

कार्यसूची मद सं .6:- परिचालन और रखरखाव के मुद्दों के संबंध में एसडीएफ-VIII के लिए सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव।

एसडीएफ VIII के यूनिट धारकों ने एसडीएफ VIII इमारत के संचालन और रखरखाव के संबंध में कई मुद्दों की सूचना दी और यह भी सुझाव दिया कि वे एक सहकारी समिति बनाना चाहते हैं जो इमारत के दिनप्रतिदिन के संचालन - और रखरखाव की देखभाल करेगी।

निर्णय:- विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने सरकारी पट्टे वाली इमारत में सोसायटी के गठन के लिए कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया और तब तक यूनिट धारकों को इमारत की संरचना को प्रभावित किए बिना इमारत के दैनिक रखरखाव का कार्य स्वयं करने की अनुमति दी।

कार्यसूची मद सं .7:- बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और उसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मत/प्रतिस्थापना।

बीएफसी बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2009 में एमआईडीसी द्वारा किया गया था और एमआईडीसी के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ सीपज़सेज़ प्राधिकरण द्वारा इसका - रखरखाव किया जाता है। सीपज़ के लिए एसपीए होने के

details/quantities before the Tender Evaluation Committee for examination and decision in the matter as per the terms and conditions of RFP/Contract Agreement. All decision taken by TEC in the matter of Mega CFC have been placed before Authority for confirmation.

Decision: - After deliberation, the Authority confirmed the decision taken by TEC in respect of additional work and/ or additional quantity for the Mega CFC project. Further, Authority decided that TEC is empowered to take decisions of such nature and these matters should be put up before authority for information only.

Agenda Item No. 6:- Proposal for formation of Cooperative Society for SDF-VIII regarding operational and maintenance issues.

SDF VIII unit holders have reported a number of issues regarding the operation and maintenance of the SDF VIII building and have also suggested that they wish to form a co-operative society that will look after the day-to-day operation and maintenance of the building.

Decision: - After deliberation, the Authority directed to obtain a legal opinion for formation of society in govt. leased building and till then allowed the unit holder to undertake the day to day maintenance of the building on their own without affecting the structure of the building.

Agenda Item No. 7:- Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & its DG Set at BFC Building.

BFC Building was constructed by MIDC in 2009 and is maintained by SEEPZ SEZ Authority with technical guidance from MIDC. MIDC, being SPA for SEEPZ, was asked to provide the DPR on 29.06.2023 for execution of

147

नाते एमआईडीसी को कार्य के निष्पादन के लिए 29.06.2023 को डीपीआर प्रदान करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, उन्होंने बीएफसी बिल्डिंग फायर सिस्टम और इसके डीजी सेट की मरम्मत के लिए लगभग 72,28,000/- रुपये का एक अस्थायी अनुमान बताया है।

बीएफसी भवन के निरीक्षण के बाद श्री वीएन सुपनेकर के साथ बैठक (आपदा प्रबंधन सलाहकार) आयोजित की गई और उनकी राय के अनुसार, डीजी सेट, फायर पाइप से लेकर अग्निशामक यंत्र, स्प्रिंकलर, फायर अलार्म सिस्टम आदि को बदलने के लिए एक समग्र अभ्यास की आवश्यकता है। आवश्यक व्यापक कार्य को देखते हुए, उन्होंने एमआईडीसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।

निर्णय: विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और इसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मत/प्रतिस्थापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद सं .8:- सीप्लसेज़, अंधेरी (पू), मुंबई में कार्यों के लिए पीएसयू पीएमसीमेसर्स वैपकांस लिमिटेड को शामिल करने का प्रस्ताव।

जीएफआर 2017 के नियम 133 (3) के संदर्भ में कार्यों के लिए पीएसयू की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति 14 दिसंबर, 2023 को सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी और 27 दिसंबर, 2023 को खोली गई थी। ईओआई को कुल 06 (छह) आवेदन प्राप्त हुए। निविदा मूल्यांकन समिति (ने बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन किया विमर्श के बाद सर्वसम्मति से ईओआई और उचित विचार में वांछित कार्यों के लिए मेसर्स वैपकांस लिमिटेड को शामिल करने का निर्णय लिया।

निर्णय: विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने सीप्लसेज़ में - मेसर्स वैपकांस - कार्यों के लिए पीएसयू पीएमसी लिमिटेड को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

the work. Accordingly, they have conveyed a tentative estimate for Repair of BFC Building Fire System & its DG Set amounting to approx. Rs. 72, 28,000/-.

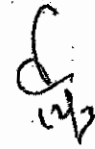
Meeting was conducted with Shri. V.N Supanekar (Disaster Management Consultant) after his inspection of BFC Bldg. and as per his opinion, it requires a holistic exercise right from changing DG Set, fire pipes to fire extinguishers, sprinklers, fire alarm system, etc. Looking at the exhaustive work required to be carried out, he has advised to proceed with DPR submitted by MIDC.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal for Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & it's DG Set at BFC Building.

Agenda Item No. 8:- Proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ Andheri (E), Mumbai.

The Expression of Interest for engagement of PSU for works in terms of Rule 133 (3) of GFR 2017 was published on CPP Portal on 14th December, 2023 and was opened on 27th December, 2023. The EoI received a total of 06 (Six) applications. The Tender Evaluation Committee evaluated the applications submitted by the bidders and after due deliberation decided with consensus to engage M/s. WAPCOS Ltd for the desired works in EoI.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ.



कार्यसूची मद सं .9:- मेसर्स एसपीएसपीएल को सुरक्षा जनशक्तिसंविदा प्रदान करना और एल-2 बोलीदाता मेसर्स एसआईएसपीएल द्वारा उनके खिलाफ शिकायत के बारे में जानकारी।

प्राधिकरण को एल1 बोलीदाता के रूप में मेसर्स एसपीएसपीएल को सुरक्षा मैन पावर सेवा संविदा दिए जाने के बारे में सूचित किया गया था। लेकिन L-2 बोलीदाता ने L-1 बोलीदाता के दस्तावेजों के बारे में शिकायत की। मेसर्स एसपीएसपीएल ने औचित्य प्रदान किया और बीएमसी लाइसेंस की प्रामाणिकता की पुष्टि की। हालाँकि, सेवा प्रदाता ने बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आवेदन में टाइपोग्राफिकल त्रुटि को स्वीकार किया, माफी मांगी और सुनिश्चित किया कि भविष्य में गलतियाँ नहीं होंगी।

प्राधिकरण को श्री चेतन सिंह से प्राप्त धमकी भरे कॉल के संबंध में एक अन्य मुद्दे के बारे में भी सूचित किया गया था, जो जी7 सिक्योरिटी सर्विसेज में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर होने का दावा करते हैं और मेसर्स एसपीएसपीएल ने इस संबंध में श्री चेतन सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

निर्णय:- विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने सुरक्षा जनशक्ति संविदा के संबंध में अद्यतनों को नोट किया।

कार्यसूची मद सं .10:- सभी बकाया शुल्कों यानी किराया बकाया, रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क आदि पर लगाए गए ब्याज और जुमनि की छूट के लिए अनुरोध।

8 यूनिटों ने विभिन्न अपीलों के माध्यम से अदालत के समक्ष वसूली नोटिसबेदखली आदेश जारी करने पर /आदेश/ विवाद किया था, जिन्हें बाद में 22.12.2020 के फैसले के माध्यम से समान अवलोकन के साथ निपटाया गया था और मामलों को सीएनसेज प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ - वापस भेज दिया गया कि वे उनके सामने मौजूद सामग्री पर विचार करें और एक तर्कसंगत आदेश पारित करें। तदनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई पर स्पीकिंग के आदेश जारी

Agenda Item No. 9:- Award of Security manpower contract to M/s SPSPL and information about complaint against them by L2 bidder M/s. SISPL.

The Authority was informed about the awarded of Security man power service contract to M/s SPSPL as a L1 bidder. But the L2 bidder complained about the L1 bidder's documents. M/s SPSPL provided justification and confirmed the authenticity of the BMC license. However, the service provider admitted to a typographical error in the Bombay Shop and Establishment License application, apologizing and ensuring future mistakes will not occur.

Authority was also informed about another issue regarding the threatening call received from Mr. Chetan Singh, who claims to be the Sr. Marketing Manager at G7 Security Services and M/s SPSPL have filed police complaint against Mr. Chetan Singh in this regard.

Decision: After deliberation, the Authority noted the updates in respect of security Manpower Contract.

Agenda Item No. 10:- Request for waiver of interest and penalty levied on all outstanding charges i.e. rental dues, maintenance charges, service charges etc.

8 Units had disputed the issuance of recovery notices/orders/Eviction orders before the Court of law vide Misc Appeals which were subsequently disposed off vide Judgment dated 22.12.2020 with similar observation and matters were remanded back to SEEPZ SEZ Authority with directions to consider the material before them and pass a reasoned order.

[Handwritten signature]

किए गए। हालांकि, कुल 8 यूनिटों में से केवल 3 यूनिटों ने उपपट्टा समझौते के निष्पादन और लीज किराए के बकाया - भुगतान के संबंध में संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सिटी सिविल कोर्ट मुंबई के समक्ष विविध अपील को प्राथमिकता दी है। अन्य 5 यूनिटों ने निर्देशानुसार भुगतान कर दिया है।

प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि कुछ यूनिट धारकों ने दिनांक 01.02.2024 के पत्र के माध्यम से सभी बकाया शुल्कों यानी किराया बकाया, रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क आदि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए अनुरोध किया था और उन यूनिटों को भी, जिन्हें सीपज़-सेज़ प्राधिकरण से कोई बेदखली का आदेश नहीं मिला था।

निर्णय:- इस मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्याज की माफी और मुकदमेबाजीके मुकाबले इसके लाभों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्राधिकरण ने सेज़ प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 7(6) पर चर्चा की जो निर्दिष्ट करता है कि-

"प्राधिकरण के पास परिसंपत्तियों और सेवाओं के संबंध में अपरिवर्तनीय पट्टा किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क को बट्टे खाते में डालने की शक्तियां होंगी, बशर्ते कि एक लाख रुपये से अधिक की कोई भी हानि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ होगी।"

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह चर्चा की गई थी कि 1 लाख रुपये से ऊपर की राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय मंत्रालय से अनुमोदन के अधीन है, हालांकि नियम में किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क का उल्लेख है और "ब्याज" पर कोई प्रयोज्यता नहीं दिखाई देती है और प्राधिकरण ने चर्चा की कि 'ब्याज लगाना' इस खंड का हिस्सा नहीं है। हालांकि, विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि किसी भी लाभ की एकरूपता के लिए एक उचित योजना की परिकल्पना की आवश्यकता है। और ऐसे सभी मामलों को समान रूप से निपटारा जाना चाहिए।

Accordingly after personal hearing, speaking orders were issued. However, out of the total 8 units only 3 Units have preferred Misc. Appeal before City Civil Court Mumbai challenging the said orders passed by Estate Officer w.r.t. execution of sublease agreement and the payment of outstanding dues towards the lease rent. The other 5 Units have made the payment as per the directions.

The Authority was informed that some Unit holders vide letter dated 01.02.2024 requested for waiver of interest and penalty levied on all outstanding charges i.e. rental dues, maintenance charges, service charges etc. and also to those units which did not receive any eviction order from the SEEPZ SEZ Authority.

Decision: - The issue was discussed at length from various aspects. Waiver of interest and its benefits over litigation were also discussed. Further Authority discussed Rule 7(6) of SEZ Authority Rules, 2009 which specifies that-

"Authority shall have the powers to write off irrecoverable lease rent, licence fee and other user charges in respect of assets and services Provided that any write-off losses beyond the sum of rupees one lakh shall be with prior approval of the Central Government."

As per above provision it was discussed that the write off above Rs 1 Lakh are subject to the approval from Ministry, however the rule mentions of rent, license fee and other user charges and there appears no applicability on "interest" and Authority discussed 'levy of interest' is not a part of this clause. However, Development Commissioner suggested that for uniformity of any benefits, there is a requirement of envisaging a proper scheme. And all such matters should be dealt with uniformly. Therefore, it was decided that in order to put an end to the ongoing litigations

इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि कुछ यूनिट धारकों द्वारा एमआईडीसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर उनके परिसर के किराए की व्याख्या को लेकर चल रही मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए, लंबित बकाया राशि पर ब्याज की छूट के लिए विभिन्न अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर एक माफी योजना तैयार की जानी चाहिए, जो प्राधिकरण के अवरोधित फंड की वसूली के लिए एसईजेड प्राधिकरण नियमों द्वारा भी वर्जित नहीं है। उक्त योजना को प्राधिकरण की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाये। इसमें मुकदमा दायर करने वाले वादियों के साथ अन्य यूनिट धारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका किराया भी उनके समान बकाया है। इस योजना को सीपज़ में व्यापार सुविधा के हित में प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक प्रगतिशील निर्णय माना जाना चाहिए और 30 दिनों की संक्षिप्त अवधि में एक बार मूल्यांकन होना चाहिए। इस मामले में कानूनी राय लेने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यसूची मद सं .11:- सार्वजनिक परिसर अनधिकृत) अधिनियम (कब्जेदारों की बेदखली, 1971 दिनांक 05.12.2023 की धारा 7 की उपधारा 3) के तहत वसूली नोटिस जारी करने पर अद्यतन स्थिति।

प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि एसडीएफ, जी एंड जे कॉम्प्लेक्स, टॉवर I और II, बहुमंजिला इमारतों और भूखंडों में स्थित परिसर के उपयोग के लिए यूनिट धारकों से किराया अग्नि उपकरण एकत्र / सेवा शुल्क / बीएमसी / किया जाना है। हालांकि, कुछ यूनिट धारकों ने उनसे बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भारी बकाया किराये का भुगतान नहीं किया था। इसलिए 05.12.2023 को 18 यूनिट धारकों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए, जिनका बकाया 5 लाख रुपये से अधिक था और 6 महीने से अधिक लंबित था। प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पीएच प्रदान किया जा रहा है और यूनिटों से भुगतान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

by some unit holders over interpretation of rent of their premises based on an allotment letter issued to them by MIDC, an Amnesty scheme should be formulated on lines of various other Govt. departments, for waiver of interest on pending dues, which is not barred by SEZ Authority Rules and also to recover the block funds of the Authority. The said scheme should be placed before Authority in its next meeting. It should also cover the other unit holders whose rent, are also due without equating them with the litigants. This scheme should be perceived as a progressive decision taken by Authority in the interest of trade facilitation at SEEPZ and should be one time measure for a brief period of 30 days. It was also decided to take a legal opinion in this matter.

Agenda Item No. 11:- Updated status on the issuance of Recovery Notices under sub-section (3) of Section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 dated 05.12.2023.

The Authority was informed that rent/BMC/Service Charges/Fire Cess are to be collected from the Unit Holders for usage of the premises located in SDFs, G&J Complex, Tower I&II, Multistoried Bldgs. and Plots. However, some of the Unit holders had not paid huge outstanding rental dues inspite of repeated requests made to them. Hence Recovery Notices were issued to 18 nos. of Unit Holders on 05.12.2023 whose outstanding dues were more than Rs. 5 lakhs and pending more than 6 months. Authority was also appraised that PH is being granted and Units are being requested to make the payment.

12/3

निर्णय:- विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने रिकवरी नोटिस जारी करने और तदनुसार शुरू की गई कार्रवाई पर अद्यतन स्थिति नोट की।

तालिका कार्यसूची मद सं.1:- प्रवेश गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन पर अद्यतन स्थिति।

प्राधिकरण को प्रवेश एप्लीकेशन के चरणवार कार्यान्वयन के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि, 1 फरवरी 2024 तक आवेदन में किए गए परिवर्तनों के साथ स्रोत कोड 05 फरवरी 2024 को एडीसी आईटी को सौंप दिए गए हैं और स्टोर रूम की अभिरक्षा में रखे गए हैं। जैसे ही डेवलपर यानी मेसर्स वीएएमएस सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम को अपडेट करेगा, बाद के अपडेट के लिए सोर्स कोड सौंप दिए जाएंगे।

यह दोहराया गया कि पुराने गेट पास का आवेदन 1 फरवरी 2024 से बंद कर दिया गया है। यूनिट के पुराने गेटपास सिस्टम वॉलेट में शेष राशि और यूनिट कर्मचारियों के वैध पुराने गेटपास की आनुपातिक राशि, जो प्रवेश गेटपास सिस्टम के कार्यान्वयन के बाद बंद हो गई है, को यूनिट के नए प्रवेश गेटपास सिस्टम वॉलेट में स्थानांतरित किया जाएगा।

यह अवगत कराया गया कि प्रवेश गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए गेट नंबर 1, 2 और 3 पर अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकता की खरीद के प्रस्ताव को 09 अगस्त 2023 को आयोजित 62वीं प्राधिकरण बैठक में लगभग मंजूरी दे दी गई थी। लागत 7,00,000/- रुआवश्यक प्रारंभिक हार्डवेयर खरीद लिया गया है और एप्लीकेशन का परीक्षण कार्यान्वयन कर लिया गया है।

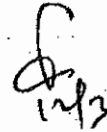
Decision: - After deliberation, the Authority noted the updated status on the issuance of Recovery Notices and action initiated accordingly.

Table Agenda Item No.1:- Updated Status on the implementation of PRAVESH Gate pass system.

The Authority was informed about the Phase wise Implementation of Pravesh Application. It was also informed that, the source codes with the changes made in the application till 1st February 2024 have been handed over to ADC IT on 05th February 2024 and kept in store room custody. The source codes for subsequent updates will be handed over as soon as developer i.e. M/s VAMS Safeguard Pvt Ltd updates the system.

It was iterated that Old Gate Pass application has been discontinued from 1st February 2024. The balance amount in Unit's old gate pass system wallet and the proportionate amount of valid old gate passes of unit employees which are discontinued after the implementation of PRAVESH Gatepass system to be transferred in Unit's New Pravesh Gatepass System Wallet.

It was apprised that the proposal for procurement of additional hardware requirement at gate no. 1, 2 & 3 for implementation of PRAVESH Gate pass system was approved in the 62nd Authority meeting held on 09th Aug 2023 with an approx. cost of Rs. 7,00,000/-. Initial hardware required had been purchased and test implementation of application has been done.



निर्णय:- विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण-ने प्रस्ताव की सिफारिशों को मंजूरी दे दी:

1. 25 सितंबर 2023 से क्लाउड शुल्क का भुगतान किया जा सकता है क्योंकि प्रवेश गेट पास एप्लिकेशन 25 सितंबर 2023 से आंशिक रूप से लागू किया गया है और क्लाउड सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
2. एडीसी की सिफारिश (आईटी और सुरक्षा) के अनुसार गोलाइव और सोर्स कोड हैंडओवर के लिए भुगतान की 30% राशि को यूनिटों द्वारा सूचित की गई सभी कमियों के सुधार तक रोका जा सकता है और 70% राशि समान मील के (र के लिए पिछले सभी भुगतान सहित पत्र वितरित की जा सकती है।
3. जैसा कि सूचित किया गया है कि तीसरे परिवर्तन अनुरोधों की सभी आवश्यकताओं का परीक्षण किया गया है, तदनुसार, बीटा परीक्षण शुल्क यानी तीसरे परिवर्तन अनुरोधों के लिए कार्य आदेश का 30% वितरित किया जाना है।
4. यूएटी यूनिटों और एडीसी की (आईटी एवं सुरक्षा) सिफारिश के बाद पूरी राशि जारी की जाएगी।

तालिका कार्यसूची मद सं 2:- प्रवेश एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गेट (नया क्यूआर कोड गेटपास सिस्टम) नंबर 1, 2 और 3 पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंडोर/आउटडोर एक्सेस पॉइंट का प्रस्ताव।

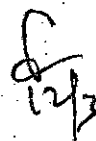
प्राधिकरण को सूचित किया गया कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रदान करके प्रवेश एक्सेस प्रबंधन प्रणाली नई) के सुचारू संचालन के लिए (क्यूआर कोड गेटपास प्रणाली गेट नंबर 1, 2 और 3 पर निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। सभी गेटों पर एक्सेस प्वाइंट लगाने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज और सुरक्षित हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की खरीद (एक्सेस पॉइंट) GeM पोर्टल के माध्यम से 22,00,000/- रुपये की अनुमानित लागत पर की जा सकती है।

Decision: - After deliberation, the Authority approved the recommendations of the proposal:

1. Cloud charges from 25th September 2023 may be disbursed as Pravesh Gate Pass Application has been partially implemented from 25th September 2023 and cloud services are being utilized.
2. As per recommendation by the ADC (IT & Security) 30 % amount of the payment milestone for Go-live and source code hand over may be held up till rectification of all shortcomings being informed by units and 70% amount (inclusive of all past payment for the same milestone) may be disbursed.
3. As informed that all requirements of 3rd change requests have been tested, accordingly, beta testing charges i.e. 30% of the work order for 3rd change request to be disbursed.
4. Complete amount will be released after recommendation by UAT Units and ADC (IT & Security).

Table Agenda Item No.2:- Proposal of indoor/outdoor Access point (AP) for internet connection at Gate no. 1, 2 & 3 for Pravesh Access management system (New QR code gatepass system).

The Authority was informed that seamless internet connectivity is essential at Gate no. 1, 2 & 3 for smooth working of Pravesh Access management system (New QR code gatepass system) by way of providing wireless Access point. After the installation of Access points at all gates, the internet connectivity will be fast and secure. The purchase of (Access point) WIFI for internet connectivity can be done via GeM portal at estimated cost of Rs. 22,00,000/-.



निर्णय:- विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से इसके लिए उचित अनुमानित लागत का पता लगाने का निर्देश दिया और उपरोक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने तक वैकल्पिक इंटरनेट समाधान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

अन्य:

उपरोक्त एजेंडे के अलावा, एमआईडीसी और अन्य एजेंसियों के पास लंबित परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने वर्तमान में चर्चा के तहत लंबित परियोजनाओं के लिए वैपकॉस (WAPCOS) को शामिल करने का निर्णय लिया।

Decision: - After deliberation, the Authority deferred the proposal and directed to find out appropriate estimated cost for the same through market survey and directed to arrange alternative internet solution till finalization of above proposal.

Others:


Apart from above Agenda, there was a discussion on projects pending with MIDC & other Agencies. After deliberations, Authority decided to engage WAPCOS for the pending projects currently under discussion.

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

यह सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.



12.03.24

(सी. पी. एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़ सेज़,
सदस्य/सचिव

ACTION TAKEN REPORT OF 65th AUTHORITY MEETING DATED. 07.02.2024

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
Finance (Account & Procurement) Division			
1	<p>सीप्लसेज़ प्राधिकरण के अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण में मासिक व्यय का विवरण, व्यय का प्रतिशत एवं शेष का लेखाजोखा - प्रस्तुत करना।</p> <p>Submission of Monthly expenditure accounts percentage of expenditure and balance in the approved annual financial statement of the SEZ Authority.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, समिति ने 01-04-2023 से 03.02.2024 तक बजट के उपयोग का विवरण नोट किया और आगे किए गए व्यय की बेहतर तुलना के लिए उन परियोजनाओं का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके लिए किए गए प्रावधानों की तुलना में बेहतर प्रावधान किए गए थे।</p> <p>After Deliberation, the Committee noted the details of utilization of budget from 01-04-2023 to 03.02.2024 and further directed to submit individual details of the projects for which the provisions were made for better comparison of the expenditure done vis-à-vis provisions made.</p>	<p>Note issued to CA Section vide dated 14.03.2024</p>
2	<p>कार्य की तत्काल प्रकृति के लिए तत्काल उपयोग के लिए 30,000/- रुपये की अग्रदाय राशि अग्रिम नकद / बढ़ाने का प्रस्ताव, जिसे फिर से 1,00,000/- रुपये पर वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>Proposal for increase Imprest/advance cash of Rs. 30,000/- for immediate usage for urgent nature of work to Rs. 1,00,000/-.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के लिए तत्काल उपयोग के लिए 1,00,000/- रुपये की अग्रिम नकद राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्राधिकरण ने अग्रदाय निधि के माध्यम से किए गए व्यय का मासिक विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।</p> <p>After deliberation, the Authority approved the proposal for increase of Imprest/advance cash of Rs. 1,00,000/- for immediate usage for urgent nature of work. The Authority directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority in its meetings.</p>	<p>Noted and Agenda is placed in ensuing meeting.</p>

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
3	<p>प्राधिकरण निधि, 2023-24 से मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को 10,41,662/- रुपये का भुगतान किया गया।</p> <p>Payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण निधि, 2023-24 से 10,41,662/- रुपये के भुगतान को मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि भारत सरकार के बजट से रिफंड के बाद उसे जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।</p> <p>After deliberation, the Authority approved the payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24 and directed that after refund from the Government of India budget the same should be placed before the Authority for information.</p>	<p>Note issued to Admin section vide note dated 14.03.2024</p>
4	<p>"स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो + छोटी अवधि के 2 वीडियो (का प्रस्ताव।</p> <p>Proposal for 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikasit Bharat".</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, समिति ने मेसर्स ग्रीन सिग्नल एंटरटेनमेंट से "स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियो की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति (दे दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता और व्यावसायिकता साबित कर दी थी। हाल ही में उन्होंने मेगा सीएफसी और एनईएसटी01 के उद्घाटन के लिए बहुत ही कम समय में गुणवत्तापूर्ण वीडियो उपलब्ध कराया था।</p> <p>After deliberation, the Committee approved the proposal for procurement of 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikshit Bharat" from M/s Green Signal Entertainment as they had proved their competence and professionalism by providing quality video in recent past at a very short notice for Mega CFC and NEST 01 inauguration.</p>	<p>Noted</p>
5	<p>मेगा सीएफसी में टेंडर बीओक्यू से परे अतिरिक्त कार्यों और मदों के लिए स्वीकृति।</p> <p>Approval for additional</p>	<p>विचारके बाद विमर्श-, प्राधिकरण ने मेगा सीएफसी परियोजना के लिए अतिरिक्त कार्य औरया अतिरिक्त मात्रा के संबंध में टीईसी / द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की। इसके</p>	<p>Noted</p>

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
	works and items beyond the Tender BoQ at Mega CFC.	<p>अलावा, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीईसी को ऐसी प्रकृति का निर्णय लेने का अधिकार है और इन मामलों को केवल जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।</p> <p>After deliberation, the Authority confirmed the decision taken by TEC in respect of additional work and/ or additional quantity for the Mega CFC project. Further, Authority decided that TEC is empowered to take decisions of such nature and these matters should be put up before authority for information only.</p>	
6	<p>परिचालन और रखरखाव के मुद्दों के संबंध में एसडीएफ-VIII के लिए सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव।</p> <p>Proposal for formation of Cooperative Society for SDF-VIII regarding operational and maintenance issues.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सरकारी पट्टे वाली इमारत में सोसायटी के गठन के लिए कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया और तब तक यूनिट धारकों को इमारत की संरचना को प्रभावित किए बिना इमारत के दैनिक रखरखाव का कार्य स्वयं करने की अनुमति दी।</p> <p>After deliberation, the Authority directed to obtain a legal opinion for formation of society in govt. leased building and till then allowed the unit holder to undertake the day to day maintenance of the building on their own without affecting the structure of the building.</p>	A legal opinion obtained.
7	<p>बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और उसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मतप्रतिस्थापन।/</p> <p>Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & its DG Set at BFC Building.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और इसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मत/ प्रतिस्थापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।</p> <p>After deliberation, the Authority approved the proposal for Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & it's DG Set at BFC Building.</p>	<p>Noted.</p> <p>Administrative approval is under approval before issuance.</p>
8	सीप्लसेज़-, अंधेरी (पू), मुंबई में कार्यों के लिए	विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सीप्ल-मेसर्स -सेज़ में कार्यों के लिए पीएसयू पीएमसी	Noted. .

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
	<p>पीएसयू पीएमसीमेसर्स - वैपकॉस लिमिटेड को शामिल करने का प्रस्ताव।</p> <p>Proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ Andheri (E), Mumbai.</p>	<p>वैपकॉस लिमिटेड को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।</p> <p>After deliberation, the Authority approved the proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ.</p>	
9	<p>मेसर्स एसपीएसपीएल को सुरक्षा जनशक्तिसंविदा प्रदान करना और एल-2 बोलीदाता मेसर्स एसआईएसपीएल द्वारा उनके खिलाफ शिकायत के बारे में जानकारी।</p> <p>Award of Security manpower contract to M/s SPSPL and information about complaint against them by L2 bidder M/s. SISPL.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद, प्राधिकरण ने सुरक्षा जनशक्ति संविदा के संबंध में अद्यतनों को नोट किया।</p> <p>After deliberation, the Authority noted the updates in respect of security Manpower Contract.</p>	Noted
10	<p>सभी बकाया शुल्कों यानी किराया बकाया, रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क आदि पर लगाए गए ब्याज और जुमाने की छूट के लिए अनुरोध।</p> <p>Request for waiver of interest and penalty levied on all outstanding charges i.e. rental dues, maintenance charges,</p>	<p>इस मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्याज की माफी और मुकदमेबाजीके मुकाबले इसके लाभों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्राधिकरण ने सेज़ प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 7(6) पर चर्चा की जो निर्दिष्ट करता है कि-</p> <p>"प्राधिकरण के पास परिसंपत्तियों और सेवाओं के संबंध में अपरिवर्तनीय पट्टा किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क को बढ़े खाते में डालने</p>	Letter to Law Ministry seeking legal opinion under submission.

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
	service charges etc.	<p>की शक्तियां होंगी, बशर्ते कि एक लाख रुपये से अधिक की कोई भी हानि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ होगी।"</p> <p>उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह चर्चा की गई थी कि 1 लाख रुपये से ऊपर की राशि को बढ़े खाते में डालने का निर्णय मंत्रालय से अनुमोदन के अधीन है, हालांकि नियम में किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क का उल्लेख है और "ब्याज" पर कोई प्रयोज्यता नहीं दिखाई देती है और प्राधिकरण ने चर्चा कि की 'ब्याज लगाना' इस खंड का हिस्सा नहीं है। हालांकि, विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि किसी भी लाभ की एकरूपता के लिए एक उचित योजना की परिकल्पना की आवश्यकता है। और ऐसे सभी मामलों को समान रूप से निपटाया जाना चाहिए। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि कुछ यूनिट धारकों द्वारा एमआईडीसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर उनके परिसर के किराए की व्याख्या को लेकर चल रही मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए, लंबित बकाया राशि पर ब्याज की छूट के लिए विभिन्न अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर एक माफी योजना तैयार की जानी चाहिए, जो प्राधिकरण के अवरोधित फंड की वसूली के लिए एसईजेड प्राधिकरण नियमों द्वारा भी वर्जित नहीं है। उक्त योजना को प्राधिकरण की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाये। इसमें मुकदमा दायर करने वाले वादियों के साथ अन्य यूनिट धारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका किराया भी उनके समान बकाया है। इस योजना को सीप्ल में व्यापार सुविधा के हित में प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक प्रगतिशील निर्णय माना जाना चाहिए और 30 दिनों की संक्षिप्त अवधि में एक बार मूल्यांकन होना चाहिए। इस मामले में कानूनी राय लेने का भी निर्णय लिया गया।</p> <p>The issue was discussed at length from various aspects.</p>	

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
		<p>Waiver of interest and its benefits over litigation were also discussed. Further Authority discussed Rule 7(6) of SEZ Authority Rules, 2009 which specifies that-</p> <p style="text-align: center;"><i>“Authority shall have the powers to write off irrecoverable lease rent, licence fee and other user charges in respect of assets and services Provided that any write-off losses beyond the sum of rupees one lakh shall be with prior approval of the Central Government.”</i></p> <p>As per above provision it was discussed that the write off above Rs 1 Lakh are subject to the approval from Ministry, however the rule mentions of rent, license fee and other user charges and there appears no applicability on "interest" and Authority discussed 'levy of interest' is not a part of this clause. However, Development Commissioner suggested that for uniformity of any benefits, there is a requirement of envisaging a proper scheme. And all such matters should be dealt with uniformly. Therefore, it was decided that in order to put an end to the ongoing litigations by some unit holders over interpretation of rent of their premises based on an allotment letter issued to them by MIDC, an Amnesty scheme should be formulated on lines of various other Govt. departments, for waiver of interest on pending dues, which is not barred by SEZ Authority Rules and also to recover the block funds of the Authority. The said scheme</p>	

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
		<p>should be placed before Authority in its next meeting. It should also cover the other unit holders whose rent, are also due without equating them with the litigants. This scheme should be perceived as a progressive decision taken by Authority in the interest of trade facilitation at SEEPZ and should be one time measure for a brief period of 30 days. It was also decided to take a legal opinion in this matter.</p>	
11	<p>सार्वजनिक परिसर अनधिकृत) (कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम, 1971 दिनांक 05.12.2023 की धारा 7 की उपधारा)3) के तहत वसूली नोटिस जारी करने पर अद्यतन स्थिति।</p> <p>Updated status on the issuance of Recovery Notices under sub-section (3) of Section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 dated 05.12.2023.</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने रिकवरी नोटिस जारी करने और तदनुसार शुरू की गई कार्रवाई पर अद्यतन स्थिति नोट की।</p> <p>After deliberation, the Authority noted the updated status on the issuance of Recovery Notices and action initiated accordingly.</p>	Noted
Table Agenda no. 1	<p>प्रवेश गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन पर अद्यतन स्थिति।</p> <p>Updated Status on the implementation of PRAVESH Gate pass system.</p>	<p>विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण-ने प्रस्ताव की सिफारिशों को मंजूरी दे दी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 25 सितंबर 2023 से क्लाउड शुल्क का भुगतान किया जा सकता है क्योंकि प्रवेश गेट पास एप्लिकेशन 25 सितंबर 2023 से आंशिक रूप से लागू किया गया है और क्लाउड सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। 2. एडीसी की (आईटी और सुरक्षा) सिफारिश के अनुसार गोलाइव - और सोर्स कोड हैंडओवर के लिए 	Satisfactory note issued vide dated 12.03.2024

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
		<p>भुगतान की 30% राशि को यूनिटों द्वारा सूचित की गई सभी कमियों के सुधार तक रोका जा सकता है और 70% राशि समान मील के पत्थर के लिए) (पिछले सभी भुगतान सहित वितरित की जा सकती है।</p> <p>3. जैसा कि सूचित किया गया है कि तीसरे परिवर्तन अनुरोधों की सभी आवश्यकताओं का परीक्षण किया गया है, तदनुसार, बीटा परीक्षण शुल्क यानी तीसरे परिवर्तन अनुरोधों के लिए कार्य आदेश का 30% वितरित किया जाना है।</p> <p>4. यूएटी यूनिटों और एडीसी आईटी) की सिफारिश के बाद (एवं सुरक्षा पूरी राशि जारी की जाएगी।</p> <p>After deliberation, the Authority approved the recommendations of the proposal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cloud charges from 25th September 2023 may be disbursed as Pravesh Gate Pass Application has been partially implemented from 25th September 2023 and cloud services are being utilized. 2. As per recommendation by the ADC (IT & Security) 30 % amount of the payment milestone for Go-live and source code hand over may be held up till rectification of all shortcomings being informed by units and 70% amount (inclusive of all past payment for the same milestone) may be disbursed. 3. As informed that all requirements of 3rd change requests have been tested, accordingly, beta testing charges i.e. 30% of the work order for 	

Sr. No	Name of Proposal	Decision	Action Taken
		<p>3rd change request to be disbursed.</p> <p>4. Complete amount will be released after recommendation by UAT Units and ADC (IT & Security).</p>	
<p>Table Agenda no. 2</p>	<p>प्रवेश एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम नया क्यूआर कोड गेटपास) के लिए गेट (सिस्टमनंबर 1, 2 और 3 पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंडोर/ आउटडोर एक्सेस पॉइंट का प्रस्ताव।</p> <p>Proposal of indoor/outdoor Access point (AP) for internet connection at Gate no. 1, 2 & 3 for Pravesh Access management system (New QR code gatepass system).</p>	<p>विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से इसके लिए उचित अनुमानित लागत का पता लगाने का निर्देश दिया और उपरोक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने तक वैकल्पिक इंटरनेट समाधान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।</p> <p>After deliberation, the Authority deferred the proposal and directed to find out appropriate estimated cost for the same through market survey and directed to arrange alternative internet solution till finalization of above proposal.</p>	<p>Noted</p>

MINUTES OF 65th AUTHORITY MEETING DATED 07.02.2024

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

ANDHERI (EAST), MUMBAI.

वित्त (लेखा एवं खरीद) प्रभाग

**Finance (Accounts &
Procurement) Division**

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 01

क) प्रस्ताव:

सीपज़ एसईजेड का- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

जीएफआर नियम 2017 के नियम 42 में संशोधन किया गया।

ग) अन्य जानकारी:

SEEPZ-SEZ प्राधिकरण का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण निम्नलिखित है।

घ) अनुशंसा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

यह कार्यसूची श्री जगदीश गौड़ (एलडीसी), श्री रवींद्र कुमार (सहायक), श्रीमती ब्रिजिज जो (वि.आ.का.स) और डॉ. प्रसाद वरवंटकर (संपदा अधिकारी) द्वारा तैयार की गई है।

जगदीश
22/3

रवींद्र

ब्रिजिज

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MUMBAI

AGENDA ITEM NO. 01

A. Proposal:

Proposal for approval of Annual Financial Statements for F.Y. 2024-25 of SEEPZ-SEZ

B. Relevant provision of SEZ Act, 2005 & Rules:

Rule 42 of the GFR Rule 2017 as amended.

C. Other information:

The Annual Financial Statements for FY. 2024-25 of SEEPZ-SEZ Authority is as follows:-

D. Recommendation:

Annual Financial Statements for F.Y. 2024-25 is placed before the Authority for approval.

Agenda Prepared by – Shri.Jagdish Gaur (LDC), Shri. Ravindra Kumar (Asst.), Smt. Bridget Joe (EA to DC) and Dr. Prasad Varvantkar (Estate Officer).

Splav
22/3 *ide*

राजू *BJ*

Annexure A

Human Resources

Description of Activities	Revenue Expenditure	Remark
Payment to outsource staff	4,00,00,000.00	The budget amount is calculated considering the following points:- 1. Monthly salary of outsourced staff based on Jan 2024 bill of M/S avadh business services private ltd. Of Rs 25 Lakh p.m approx would amount to 3 crores p.a. approx. However, payment for the month of March 2025 may not be paid from this budgeted head due to bills are raised by vendor in succeeding month. 2. it also includes outstanding salary for the month of Feb 24 and March 24 month amounting to Rs.50 Lakh (25L*2) 3. Amount of Rs. 50 lakh kept for contingency fund towards increment or additional personnel hired if any.
Miscellaneous Expenditure	25,00,000.00	The budget amount is calculated considering the following points:- 1. Amount of Rs 15 lakh kept for training programme if any . 2. Amount of Rs 10 lakh kept for salary/professional fees of appointment of any professional consultant.
Total	4,25,00,000.00	

Annexure B
IT capital Expenditure

Particulars of work	Budget Amount	Remark
Network operation center (NOC), Security operation center (SOC), Command & control center (CCC)	7,00,00,000	The tender for CCC and NOC SOC are under preparation. The proposal for CCC NOC & SOC is already approved.
Rise ERP Project	15,00,00,000	The project is under implementation
Pravesh Gate pass System	60,00,000	The project is under implementation. The connectivity enhancement at gates and the change request in the PRAVESH application as per the requirement of units needed to be incorporated. Purchase of IT Hardware such as mobile
IT capital expenditures	1,00,00,000	IT peripherals including computer system services switch & other IT hardware. This includes pending payment to the VAMS team for modification AMC and cloud charges.
Total (A)	23,60,00,000	

IT Revenue Expenditure

NICNET/E-office	15,00,000	The NICNET leased line services for the NIC application such as E-office gov email etc.
MPLS Line for ICE GATE	40,00,000	The dedicated MPLS (Multi protocol label switching) line connection is necessary for ICEGATE implementation in SEEPZ-SEZ
AMC for website maintenance	15,00,000	website maintenance for the timely upgradation
Software & licenses	50,00,000	Microsoft office license for 180+ users webex subscription e-scan antivirus application etc.
EOU monitoring application with AMC	10,00,000	The current application for EOU monitoring is old and outdated which is needs to be upgraded. The AMC for any further changes required.
Total (B)	1,30,00,000	

IT Miscellaneous Expenditure

Miscellaneous contingency fund	15,00,000	any adhoc requirement for the IT Section.
Total (C)	15,00,000	
Grand Total (A+B+C)	25,05,00,000	

Annexure C
Security Capital Expenditure

Particulars of work	Budget Amount	Remark
Hand Metal detector and doorframe metal detector	22,00,000	Purchase of hand held metal detector (15 nos) & door frame metal detector (12 nos) for frisking with AMC.
Baggage scanner machine with AMC	2,50,00,000	Purchase of new baggage scanner machine with AMC-12 nos.(1 large & 3 small at each gate)
Security devices	10,00,000	Mega phone torch Light HD Camera vehicle checking mirror & Hard disk etc.
Two wheeler for patrolling	5,00,000	purchase of 350 CC bike for security guard patrolling and piloting of guests (2 nos.)
Four wheeler for patrolling	12,00,000	purchase of SUV for SO and ASO patrolling (1 nos.)
IT infrastrurue- boom barrier & Flap barrier	75,00,000	It infrastructure at gate pass for the vehicle and public movement (6 nos. boom barriers & 22 flap barriers)
Arms & Ammunition	2,00,000	Purchase of rifle bullets (150 nos.) & revolver bullets (200 nos.) to be used in security training
Security capital Expenditure	10,00,000	
Total(A)	3,86,00,000	

Security Revenue Expenditure

Particulars of work	Budget Amount	Remark
Security Services Expenditure	9,00,00,000	Security service M/s. SPSPL
Security consultancy expenditure	35,00,000	M/s. Mitkat Consultancy
Walkie-Talkie expenditure	10,00,000	purchase pf new walkie-talkie machine (35+30 Extra battery)
Gust punch ready (Patrolling tool) with AMC	10,00,000	Guard patrol system for partrolling with AMC (30 point with 2 device)
patriotism ceremony expense (independence Day & Republic Day)	5,00,000	Expenditures for variopus cultural program arrangement on occasion of independence & republic day
Airtime Service expense AMC For Walkie talike	4,00,000	maintance services for walike-talkie
Infrastructural at gates	10,00,000	Railing for public movement at checking and check out washroomn renovation ladies frisking booths changing room infrastrure etc.
security training	2,00,000	Security training for government security officials
Total(B)	9,76,00,000	

Miscellaneous Expenditure

Particulars of work	Budget Amount	Remark
Miscellaneous Expenditure	12,00,000	Kept for miscellaneous work which are not specified in Revenue and capital expenditure list given above
Total(C)	12,00,000	

Grand Total(A+B+C)	13,74,00,000	
---------------------------	---------------------	--

Annexure D

Estate- Reveue Expenditure		
Description of Activities	Budget Amount	Remark
Bank Charges	16,000.00	Bank charges for the F.Y 23-24 as on 22/03/2024 is Rs. 14338. Therefore, Rs. 16000 kept on adhoc basis.
Vehicle Gate Pass and Stickers	57,000.00	same as last year
Printing & Stationery Miscellaneous	2,00,000.00	same as last year
Seepz Directory Printing	45,000.00	same as last year
Guest house maintenance	5,40,000.00	same as last year
Creche for children	16,12,300.00	Based on payment made during the F.Y 23-24 (upto Feb 2024) is Rs 14,02,000. considering inflation & trend of changes in bills received from Stree Mukti Sanghatana the 15 % increment is provided.
Internet leased line charges (TATA PRI & ISP)	13,90,000.00	same as last year
House Keeping	2,58,91,198.20	5% increase in last year provision
Vehicle Hiring & Taxi Charges	24,02,400.00	5% increase in last year provision
Refreshment	2,00,000.00	same as last year
Imprest	8,60,000.00	same as last year
Pest Control	19,00,000.00	same as last year
Water Charges	75,00,000.00	same as last year
Total (A)	4,26,13,898.20	

Annexure D

Electrical Work- Capital

Particulars of works	Budget Amount
Solar Roof Top on Each Watch tower (4 Nos.)	15,00,000
SCADA Implementation System	60,00,000
BFC Building Fire fighting System operationalization	85,00,000
Supply Installation & commissioning of damaged street light poles from Gate II to Gate II	60,00,000
Procurement of DG set for DC seepz office & BFC build	30,00,000
Total (B)	2,50,00,000

Electrical Works - Revenue	
Particulars of works	Budget Amount
Electricity Expenses (Bill)	2,50,00,000
AMC of all Elevator (Jay Bhagwan & KONE Elevator)	10,00,000
AMC of Electrical Maintenance, CCTV/PA System & DG set for SDF VIII	47,00,000
AMC of Elevators for SDF VIII	4,50,000
AMC of Air Conditioner for SDF VIII	2,50,000
AMC of Fire Fighting for SDF VIII	11,00,000
Electrical Material Purchases	10,00,000
Consultant for Assisting in Operationalising Power Distribution License	5,00,000
Miscellaneous Head	10,00,000
AMC of CCTV for SEEPZ premises	56,00,000
AMC of Lift for (SDF I -VI & GJ complex)	1,10,00,000
AMC of Electrical for SEEPZ premises	50,00,000
AMC of STP for SEEPZ Premises	15,00,000
Total (C)	5,81,00,000

Civil Works - Capital	
Particulars of works	Budget Amount
Construction of NEST 1 Building	10,00,00,000
Construction of NEST 2 Building	81,00,00,000
Construction of Mega CFC	24,00,00,000
Redevelopment of SEEPZ-SEZ Staff Colony	20,00,00,000
Reconstruction of Gate no. 02 in SEEPZ SEZ premises.	3,45,00,000
Deviation cost for SDF VIII (MIDC due)	2,00,00,000
Asides schemes (MIDC due)	4,00,00,000
Raising height of compound wall from chainage 520 to chainage 690 including razor wire fencing and 600mm dia concertina coil near M/s Sanghavi Jewels in sector VI.	27,00,000
Strengthening the partly collapsed and dilapidated compound wall near STP plot, plot no. 36, plot GJ-11 and wall near Gate no. 3	95,00,000
Total(D)	1,45,67,00,000

Annexure D

Civil Works - Revenue

Particulars of works	Budget Amount
Consultancy Fees for TDA, TPVA and SCVA	20,00,000
Repair and Renovation work of Non Processing Zone, Sector-1, SEEPZ-SEZ	18,00,000
External Structural repairing, Ducts repairing work along with replacing existing pipe lines & Painting work at BFC building SEEPZ-SEZ	40,00,000
Internal repairing & Renovation work of Development Commissioner Office, Service center building SEEPZ-SEZ	5,00,00,000
Repair/Renovation work of Gents & Ladies Toilets at Front of Post office & Central Bank in Seervice Centre Building. SEEPZ-SEZ.	7,00,000
External Repairs & waterproofing work of Secrvice Center Building	30,00,000
Emergency repair work to internal road leading to M/s Intergold & NEST 01 site at SEEPZ SEZ.	35,00,000
Emergancy repair work to internal road near NEST 01 and resealing of joints in concrete road well chowk to garbage plot.	53,00,000.00
Emergancy repair work to service road from SDF I to Mega CFC and resealing of joints in concrete road from Gate 1 to well chowk to multi-storied building.	48,00,000.00
Repairing of sewer line manhole by raising the height up to the road level and providing Fibre-reinforced plastic [FRP] manhole cover along with the frames [Phase II] at SEEPZ SEZ.	34,00,000.00
Providing and fixing fabricated MS grating/grill on the open storm water chambers and open cable ducts [Phase II] at SEEPZ SEZ.	4,50,000.00
Providing structural and civil repair works in Fire Station building in SEEPZ SEZ.	50,50,000
Providing 150mm dia DI pipeline from G&J II & III sump to SDF IV on emergancy basis.	53,00,000
Providing pumping arrangements from SDF II to SDF IV to ensure the water supply.	50,000
Construction of new sump and pump house for SDF V building in SEEPZ SEZ premises.	1,12,00,000
Emergent cleaning of gutter chambers in SEEPZ SEZ premises.	5,00,000
Providing MS Y angles with barbed wire for safety to the Mega CFC building compound wall.	1,80,000
Provision of silicon sealant in gap portion of facade glass at SDF VIII building in SEEPZ SEZ.	13,00,000
SDF VIII Mis. civil works	15,00,000
Civil AMC tools and tackles and Materials	16,00,000
Underground and overhead water tank cleaning	15,00,000
Interim repairing of Duct waste & soil pipe line plumbing & civil work repairing of sever line chambers of SDF-I & II	10,00,000
External painting to SDF-I, Middle and B-wing building portion opposite to MEGA CFC building north facing and part of SDF-II, Sector-IV, SEEPZ-SEZ.	6,50,000
Purchase of water meters for replacement of water meters	50,000
Repairing of Road in between Multistoried building and SDF-I & II	10,00,000
Total (E)	10,98,30,000

Miscellaneous Expenditure

Any Adhoc requirements	10,00,000
Total (F)	10,00,000

Grand Total(A+B+C+D+E+F)	1,69,32,43,898
---------------------------------	-----------------------

Annexure E**Administration Expenses**

Description of Activities	Budget Amount	Remark
Accounting Charges, Billing Services and Income Tax Assessment	42,00,000.00	same as last year
Internal Audit Fees	2,50,000.00	estimated on adhoc basis
Tax Audit Fees	75,000.00	Based on last year payment made to tax Auditor
CRA Audit Fees	5,51,250.00	same as last year
Labour Consultant (Individual/Firm)	30,00,000.00	same as last year
Other Professional/Consultancy Services (Horticulture/ Energy audit/ Solar / Waste Management)	1,00,00,000.00	same as last year
Legal Charges	16,00,000.00	same as last year
Development control Regulation (Architect)	50,00,000.00	same as last year
Total (A)	2,46,76,250.00	

Miscellaneous Expenditure

Miscellaneous Expenditure	15,00,000	kept on adhoc basis
Total (B)	15,00,000	
Grand Total (A+B)	2,61,76,250.00	

Budgeted Expenditure For FY2024-25

Human Resources			
Final Head	Description of Activities	Total Amount	Remark
10H120010201	Payment to outsource staff	4,00,00,000.00	For detailed calculation please refer Annexure A
10H120010301	Miscellaneous Expenditure	25,00,000.00	
	Total	4,25,00,000.00	
IT and E-Governance			
Final Head	Description of Activities	Total Amount	Remark
10I110010101	IT Capital Expenditure	23,60,00,000.00	For detailed calculation please refer Annexure B
10I110010201	IT Revenue Expenditure	1,30,00,000.00	
10I120010301	Miscellaneous Expenditure	15,00,000.00	
	Total	25,05,00,000.00	
Security			
Final Head	Description of Activities	Total Amount	Remark
10S110010101	Security Capital Expenditure	3,86,00,000.00	For detailed calculation please refer Annexure C
10S120010201	Security Revenue Expenditure	9,76,00,000.00	
10S120010301	Miscellaneous Expenditure	12,00,000.00	
	Total	13,74,00,000.00	
Estate			
Final Head	Description of Activities	Total Amount	Remark
10E120010102	Estate- Revenue Expenditure	4,26,13,898.20	For detailed calculation please refer Annexure D
10E110010401	Electrical Works - Capital	2,50,00,000.00	
10E120010401	Electrical Works - Revenue	5,81,00,000.00	
10E110010402	Civil Works - Capital	1,45,67,00,000.00	
10E120010402	Civil Works - Revenue	10,98,30,000.00	
10E120010301	Miscellaneous Expenditure	10,00,000.00	
	Total	1,69,32,43,898.20	
Administration Expenses			
Final Head	Description of Activities	Total Amount	Remark
10A120010101	Administration Exp- Revenue	2,46,76,250.00	For detailed calculation please refer Annexure E
10A120010301	Miscellaneous Expenditure	15,00,000.00	
	Total	2,61,76,250.00	
	Grand Total	2,14,98,20,148.20	

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 02

क) प्रस्ताव:

अग्रदाय के माध्यम से किया गया मासिक विवरण व्यय।

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा और सेज़ प्राधिकरण नियम, 2009 का नियम 1(1)

ग) अन्य जानकारी:

दिनांक 07.02.2024 को आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एजेंडा आइटम नं. 02, जिसमें अग्रदाय के माध्यम से किये गये व्यय का मासिक विवरण प्राधिकरण की बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। फरवरी, 2024 माह में किए गए व्यय निम्नलिखित हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

Sr No.	Date	Description	Amount (in Rs.)
1.	02.02.2024	मुंबई से नई दिल्ली तक आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग	20072.00
2	05.02.2024	नई दिल्ली में स्थानीय ड्यूटी के लिए (वाहन)	7000.00
3	05.02.2024	एयर इंडिया टिकट बुकिंग	23103.00
4	07.02.2024	राजभाषा संसद की बैठक के लिए जूट/कपास बैग की खरीद के लिए श्री संदेश संसद।	3000.00
5	13.02.2024	लाभ सत्यापन शुल्क	354.00
6	14.02.2024	एलईडी टेबल लैंप की खरीद के लिए श्री विराज मातोंडकर	1700.00
7	14.02.2024	एलईडी स्पॉट लाइट बीएफसी बिल्डिंग के लिए श्री विराज मातोंडकर	5000.00
8	14.02.2024	एससीबी में एसी आउटडोर यूनिट की मरम्मत	1800.00
9	16.02.2024	किताबों की तैयारी और ओला शुल्क के लिए प्रणव कुमार	1790.00
10	16.02.2024	मैसर्स टॉली सॉल्यूशंस	15,930.00
		Total	79,749

कार्यालय आदेश क्रमांक के अनुसार, 10/2024 अग्रदाय सीमा रुपये तक सीमित होगी। 5,000/- प्रति लेनदेन, हालांकि यह सीमा डीडीसी/जेडीसी द्वारा अनुमोदित अत्यावश्यक प्रकृति के लेनदेन पर लागू नहीं होगी (प्रतिलिपि संलग्न)।

घ. अनुशंसा :

अग्रदाय के माध्यम से किए गए मासिक विवरण व्यय को जानकारी के लिए प्राधिकारी के समक्ष रखा जाता है।

यह कार्यसूची श्री जगदीश गौड़ (एलडीसी), श्री रवींद्र कुमार (सहायक), श्रीमती ब्रिजेट जो (वि.आ.का.स) और डॉ. प्रसाद वरवंटकर (संपदा अधिकारी) द्वारा तैयार की गई है।

जगदीश
22/3

संपदा

प्रसाद

**SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
MUMBAI**

AGENDA ITEM NO. 02

A. Proposal:

Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.

B. Relevant provision of SEZ Act, 2005 and Rules:

Section of the SEZ Act, 2005 & Rule 1(1) of SEZ Authority Rules, 2009.

C. Other Information:

As per the Minutes of 65th Authority meeting held on 07.02.2024, Agenda Item no. 02, wherein it was directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority meeting. The following are the expenses incurred in the month of February, 2024. (Copy enclosed)

Sr No.	Date	Description	Amount (in Rs.)
1.	02.02.2024	IRCTC Ticket booking from Mumbai to New Delhi	20072.00
2	05.02.2024	For local Duty in new Delhi (vehicle)	7000.00
3	05.02.2024	Air India Ticket booking	23103.00
4	07.02.2024	Shri . Sandesh Sanas for purchase of Jute/cotton bags for Rajbhasha Parliomentory meeting.	3000.00
5	13.02.2024	Bene Validation charge	354.00
6	14.02.2024	Shri. Viraj Matondkar for purchase of LED Table lamp	1700.00
7	14.02.2024	Shri. Viraj Matondkar for LED Spot Light BFC building	5000.00
8	14.02.2024	Repair of Ac outdoor unit at SCB	1800.00
9	16.02.2024	Pranav Kumar for preparation of books and Ola charges	1790.00
10	16.02.2024	M/s. Tolly Solutions	15,930.00
		Total	79,749

As per Office Order no. 10/2024 the Imprest limit would be limited to Rs. 5,000/- per transactions; however this limit will not be applicable to transactions of urgent nature as approved by DDC/JDC.

D. Recommendation:

The Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest is placed before authority for information.

Agenda Prepared by – Shri.Jagdish Gaur (LDC), Shri. Ravindra Kumar (Asst.), Smt. Bridget Joe (EA to DC) and Dr. Prasad Varvantkar (Estate Officer).

Jagdish
22/13

रविंद्र

Dr.



Detailed Statement

Name: SEEPZ SPECIAL A/C Type: CAA
Address: Cust ID: 585852881

A/C No: 108605003693 IFSC Code: ICIC0001086
Transaction Period: From 01/02/2024 To 01/03/2024
Statement Request/Download Date: 01/03/2024

Advanced Search

Amount from: NA To NA
Cheque number from: NA To NA
Transaction Type: DC

Sr No	Tran ID	Value Date	Transaction Date	Cheque no/ RefNo	Transaction Remarks	Withdrawl (Dr)	Deposit (Cr)	Balance
1	S1768515	02-Feb-2024	02-Feb-2024		UPI/403342148928 /IRCTCTICKETBOOK/irctc.cf@hdfcba/H	20072.00	NA	13512.25
2	S3379819	04-Feb-2024	05-Feb-2024		UPI/403519149920 /UPI Pay/9818557193@payt//ICIf27cc	7000.00	NA	6512.25
3	S4891928	05-Feb-2024	05-Feb-2024		NEFT-PUNBH240365981 07-SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE	NA	23000.00	29512.25
4	S5045089	05-Feb-2024	05-Feb-2024		UPI/403624623134 /UPI Pay/airindia.bd@ici //ICi64eab	23103.00	NA	6409.25
5	S6290583	06-Feb-2024	06-Feb-2024		NEFT-PUNBH240371247 25-SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE	NA	23000.00	29409.25
6	S7442850	07-Feb-2024	07-Feb-2024		UPI/403832758403 /UPI Pay/sandeshsanas 198//ICi4b492	3000.00	NA	26409.25
7	S3804637	13-Feb-2024	13-Feb-2024		Bene validtn chrg Jan24+GST	354.00	NA	26055.25
8	S5300110	14-Feb-2024	14-Feb-2024		UPI/404558820581 /LEDTablelampddc /virajmatondkarp//	1700.00	NA	24355.25
9	S5303326	14-Feb-2024	14-Feb-2024		UPI/404558826725 /LEDSpotlightBFC/ virajmatondkarp//	5000.00	NA	19355.25
10	S5306345	14-Feb-2024	14-Feb-2024		UPI/404558833796 /repairofACoutdo/9 892434993@upi//	1800.00	NA	17555.25
11	S7354814	16-Feb-2024	16-Feb-2024		UPI/404765321810 /UPI Pay/9576491886@ ybl//ICi5ec224	1790.00	NA	15765.25

12	S7426089	16-Feb-2024	16-Feb-2024		UPI/404790549840 /UPI/ankitdayalkar05/Saraswat Bank	NA	1.00	15766.25
13	S7443714	16-Feb-2024	16-Feb-2024		UPI/404743113424 /UPI/irsprasadv@o kic/ICICI Bank/IC	NA	200.00	15966.25
14	S7500913	16-Feb-2024	16-Feb-2024		NEFT- PUNBH240478135 30-SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE	NA	100000.00	115966.25
15	S7508802	16-Feb-2024	16-Feb-2024		UPI/404799109331 /UPITransaction/tall ysolutions./IN	15930.00	NA	100036.25
16	S3839492	23-Feb-2024	23-Feb-2024		UPI/402996487577 /UPI Pay/airindia.bd@ici //ICI35694	NA	21657.00	121693.25

Legends Used in Account Statement

1. BBPS - Bharat Bill Payment Service
2. BCTT - Banking Cash Transaction Tax
3. BIL - Internet Bill payment or funds transfer to Third party
4. BPAY - Bill payment
5. CCWD - Cardless Cash Withdrawal
6. DTAX - Direct Tax
7. EBA - Transaction on ICICI Direct
8. IDTX - Indirect Tax
9. IMPS - Immediate Payment Service
10. INF - Internet fund transfer in linked accounts
11. INFT - Internal Fund Transfer (Within ICICI Bank)
12. LCCBRN CMS - Local cheque collection
13. LNPY - Linked loan payment
14. MMT - Mobile Money Transfer (Insta FT - IMPS)
15. N chg - NEFT Charges
16. NEFT - National Electronics Funds Transfer System (Other Bank Fund transfer)
17. ONL - Online Shopping transaction (Payment done on third party website)
18. PAC - Personal Accident cover
19. PAVC - Pay any Visa credit card
20. PAYC - Pay to Contact
21. RCHG - Recharge
22. SMO - Smart Money order
23. T Chg - Travel Charges
24. TOP - Mobile recharge
25. UCCBRN CMS - Upcountry cheque collection
26. VAT / MAT / NFS - Cash withdrawal at other bank ATM
27. VPS / IPS - Debit card transaction
28. BIL - To third party is for RIB
29. GIB - Tax & Statutory payment, EPFO, ESIC
30. CMS - Internet bulk payment fund trf

*You can download maximum of 2000 Transaction.

This is a system-generated statement. Hence, it does not require any signature.

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 03

क) प्रस्ताव:

प्राधिकरण मामलों से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक देने की प्रथा पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव।

(ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

धारा 34, एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 7 के साथ पठित

ग) अन्य जानकारी:

सरकारी लेखांकन - नियम 1990 के नियम 44 के अनुसार, एक वाणिज्यिक विभाग या उपक्रम सरकार के अन्य विभागों द्वारा की गई या प्रदान की गई किसी भी आपूर्ति और सेवाओं के लिए सामान्य शुल्क लगेगा और वसूला जाएगा।

दिनांक 29.11.2022 को आयोजित 56वीं प्राधिकरण बैठक में सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के लिए पारिश्रमिक देना स्वीकृत किया गया था और दिनांक 06.12.2023 को आयोजित 64वीं प्राधिकरण बैठक में विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, उप-विकास आयुक्त को भी पारिश्रमिक दिया जाना स्वीकृत किया गया। यह ध्यान में लाया गया कि सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले ऐसे पारिश्रमिक में एफआर 49 की तुलना में इस प्रथा में कुछ अस्पष्टता और असंगतता है।

तदनुसार, सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकरण निधि से मासिक पारिश्रमिक की प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना है कि, विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, उप-विकास आयुक्त ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के महीने के लिए भुगतान किए गए अपने पारिश्रमिक को पहले ही वापस कर दिया है।

घ) अनुसंधान:-

प्राधिकरण मामलों से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक देने की प्रथा पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

यह कार्यसूची श्री जनेश त्रिपाठी (एलडीसी), श्री राजेश कुमार (यूडीसी), श्री मनीष कुमार (एडीसी) और डॉ. प्रसाद वरवंटकर (संपदा अधिकारी) द्वारा तैयार की गई है।

राजेश कुमार
जनेश त्रिपाठी

मनीष

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

SEEPZ SEZ AUTHORITY
SEEPZ-SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MUMBAI

कार्यसूची मद संख्या

AGENDA ITEM NO. 03

(A) Proposal:-

Proposal to revisit the practice of awarding remuneration given to Govt employees for their work related to Authority Matters.

(B) Rules :-

Section 34 read with, Rule 7 of SEZ Authority Rule, 2009

(C) Other Information:-

As per Rule 44 of Government Accounting - Rule 1990, A commercial department or undertaking shall ordinary Charge and be charged for any supplies and services made or rendered to or by other departments of Government.

In 56th Authority Meeting held on 29.11.2022, remuneration was granted to government staff for their work and the remuneration was extended to DDC, JDC, DC in 64th Authority meeting held on 06.12.2023.

It was brought to notice that there is some ambiguity and inconsistency in this practice vis a vis FR 49 in such remuneration paid to government officers.

Accordingly, it is proposed to discontinue the practice of monthly remuneration to government employees from Authority Fund.

Further, it is to mention that, DC, JDC, DDC have already reversed the remuneration paid to them for the month of Dec 2023 & January 2024.

(D) Recommendation:

Proposal to revisit the practice of awarding remuneration given to Govt employees for their work related to Authority Matters is placed before Authority for approval.

Agenda Prepared by – Shri.Janesh Tripathi (LDC), Shri. Rajesh Kumar (UDC), Shri. Manish Kumar (ADC) and Dr. Prasad Varvantkar (Estate Officer).


Janesh T,



भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 04

क) प्रस्ताव:

मेगा सीएफसी की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव।

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 34 और सेज़ प्राधिकरण नियम 2009 का नियम 10

ग) अन्य जानकारी:

मेगा सीएफसी के निर्माण, आंतरिक कार्य और मेगा सीएफसी यूनिट के लिए खरीद मशीनरी का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। बचा हुआ छोटा-मोटा काम पूरा किया जा रहा है और जिसे 1 अप्रैल, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त परियोजना के लिए 74.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था। इसमें से 59.09 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त राशि 14.90 करोड़ रुपये है। ठेकेदारों और पीएमसी के अंतिम आरए बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित बीओक्यू (BOQ) से अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। इसलिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में सभी एजेंसियों के बिलों के अंतिम भुगतान के लिए 24.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

घ) अनुसंशा:-

मेगा सीएफसी की चल रही परियोजना का अद्यतनीकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

यह कार्यसूची श्री घनश्याम भंडारीद्वारा तैयार की गई है।

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
MUMBAI

AGENDA ITEM NO. 04

A) Proposal:

Proposal for up-dation of ongoing project of Mega CFC.

B) Relevant provision of SEZ Act, 2005 & Rules :

Section 34 of SEZ Act, 2005 and Rule 10 of SEZ Authority Rules 2009.

C) Other information :

The Civil work of construction Mega CFC, Interior Works and procurement machineries for Mega CFC unit has been completed. The minor snag works are being completed and will be finished by 1st April, 2024.

During the year 2023-24 a budget provision Rs.74.00 Crores was allocated for the said project. Out of the same, an amount of Rs.59.09 Crores has been utilized. The unutilized amount during this FY 2023-24 is Rs.14.90 Crores. The final RA bills of the contractors and PMC's are yet to be received. Further there is increase in the quantity above then the BoQ approved by the Tender Evaluation Committee. Therefore Rs.24.00 Crores in budget provision for the year 2024-25 is required of final payment of bills of all agencies.

D) Recommendation:-

The up-dation of ongoing project of Mega CFC is submitted before the Authority for consideration.

Agenda Prepared by -Shri. Ghanashyam Bhandari (Asst.)

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीप्ल-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 05

क) प्रस्ताव:

नेस्ट-02 की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 34 और सेज़ प्राधिकरण नियम 2009 का नियम 10

क) अन्य जानकारी:

नेस्ट-02 का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। ईपीसी ठेकेदार द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार परियोजना अगस्त, 2024 में पूरी हो जाएगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त परियोजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था। इसमें से 18.03 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त राशि 81.96 करोड़ रुपये है। आरए बिल जारी करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में 81.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

घ) अनुसंशा:-

नेस्ट-02 की चालू परियोजना का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कार्यसूची श्री घनश्याम भंडारीद्वारा तैयार की गई है।



SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
MUMBAI

AGENDA ITEM NO. 05

A) Proposal:

Proposal for up-dation of ongoing project of NEST-02

B) Relevant provision of SEZ Act, 2005 & Rules :

Section 34 of SEZ Act, 2005 and Rule 10 of SEZ Authority Rules 2009.

C) Other information :

The construction of NEST-02 is under construction. As per the scheduled given by the EPC contractor. The project will be completed on August, 2024.

During the year 2023-24 a budget provision Rs.100.00 Crores was allocated for the said project. Out of the same, an amount of Rs.18.03 Crores has been utilized. The unutilized amount during this FY 2023-24 is Rs.81.96 Crores. An amount of Rs.81.00 Crores has been proposed in budget provision for the year 2024-25 for release of RA bills.

D) Recommendation:-

The proposal for ongoing project of NEST-02 is submitted before the Authority for consideration.

Agenda Prepared by -Shri. Ghanashyam Bhandari (Asst.)

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीप्ल-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 06

क) प्रस्ताव: 1:

नेस्ट-01 की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 34 और सेज़ प्राधिकरण नियम 2009 का नियम 10

क) अन्य जानकारी:

नेस्ट-01 का निर्माण पूरा हो चुका है। बचा हुआ छोटा-मोटा काम पूरा किया जा रहा है और जिसे 1 अप्रैल, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त परियोजना के लिए 40.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था। इसमें से 31.99 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त राशि 7.99 करोड़ रुपये है। ईपीसी ठेकेदार और पीएमसी के अंतिम आरए बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित बीओक्यू की तुलना में उपरोक्त मदों में कुछ वृद्धि हुई है। इसलिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में सभी एजेंसियों के बिलों के अंतिम भुगतान के लिए 10.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

घ) अनुसंशा:-

नेस्ट-01 की चालू परियोजना का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कार्यसूची श्री घनश्याम भंडारी द्वारा तैयार की गई है।



SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
MUMBAI

AGENDA ITEM NO. 06

A) Proposal:

Proposal for up-dation of ongoing project of NEST-01

B) Relevant provision of SEZ Act, 2005 & Rules :

Section 34 of SEZ Act, 2005 and Rule 10 of SEZ Authority Rules 2009.

C) Other information :

The construction of NEST-01 has been completed. The minor snag works are being completed and will be finished by 1st April, 2024.

During the year 2023-24 a budget provision Rs.40.00 Crores was allocated for the said project. Out of the same, an amount of Rs.31.99 Crores has been utilized. The unutilized amount during this FY 2023-24 is Rs.7.99 Crores. The final RA bills of the EPC contractor and PMC are yet to be received. Further there are some increase in the items above than the BoQ approved by the Tender Evolution Committee. Therefore Rs.10.00 Crores in budget provision for the year 2024-25 is required of final payment of bills of all agencies.

D) Recommendation:-

The proposal of ongoing project of NEST-01 is submitted before the Authority for consideration.

Agenda Prepared by -Shri. Ghanashyam Bhandari (Asst.)

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

ANDHERI (EAST), MUMBAI.

संपदा प्रभाग

ESTATE Division

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 07

क) प्रस्ताव:

मेगा सीएफसी के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) से लेकर 5 वें तल तक को जीजेईपीसी को सौंपने का प्रस्ताव।

ख) सेज़ अधिनियम, 2005 और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 34 और सेज़ प्राधिकरण नियम 2009 का नियम 8

क) अन्य जानकारी:

इस कार्यालय ने दिनांक 29.01.2024 के पत्र के माध्यम से जीजेईपीसी को सूचित किया है कि:

(i) इस कार्यालय को विशेष योजना प्राधिकरण (एमआईडीसी) से दिनांक 8.01.2024 के पत्र संख्या MIDC/DE&SPA/SEEPZ के माध्यम से अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है और मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एमआईडीसी से दिनांक 05.01.2024 के पत्र संख्या I/34986/2024 और दिनांक 25.01.2024 के पत्र संख्या I/38010/2024 के माध्यम से मेगा सीएफसी, सीपज़-सेज़ की पहले फ्लोर से पांचवें फ्लोर तक के परिसर के कब्जे के लिए संबंध में फायनल फायर एनओसी प्राप्त हुई है।

(ii) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार, जीजेईपीसी को परियोजना के संचालन और कार्यान्वयन के लिए मेगा सीएफसी के पहले फ्लोर से पांचवें फ्लोर तक का क्षेत्र दिनांक 03.10.2023 के एलओए संख्या SEEPZ-SEZ/IA-I/GJEPC/1/2023-24/14367 के अनुसार अनुमोदित किया गया था और उक्त सभी फ्लोर के रखरखाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने और विभिन्न वैधानिक अनुमोदनों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) इसके अलावा, 1 फरवरी, 2024 से, जीजेईपीसी स्वयं सौंपे गए क्षेत्र के रखरखाव की लागत के लिए सभी खर्च वहन करेगी, जिसमें सौंपे गए क्षेत्र के लिए सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला किराया भी शामिल है। दिनांक 25.01.2024 के फायनल फायर स्वीकृति के अनुसार एमआईडीसी को फ्लोर-वाइज़ आवधिक अनुपालन अग्निशमन विभाग द्वारा अपने स्तर पर सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की किसी भी जिम्मेदारी के बिना सुनिश्चित किया जाना है।

(iv) इसके अलावा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एमआईडीसी से फायनल एनओसी प्राप्त होने के बाद बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 6वीं मंजिल उन्हें सौंपी जानी थी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और छठे फ्लोर पर जगह के इष्टतम उपयोग के लिए जीजेईपीसी की अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकताओं के आधार पर इन फ्लोर की प्रारंभिक योजना में कुछ बदलाव किए गए थे।

दिनांक 29.01.2024 के पत्र के जवाब में, जीजेईपीसी ने दिनांक 21.02.2024 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि:-

- (क) फायर एनओसी 15 फरवरी, 2024 को प्राप्त हुई, तदनुसार उन्हें उम्मीद है कि 15 मार्च, 2024 तक सभी फैक्ट्री लाइसेंस लागू हो जाएंगे।
- (ख) हाउसकीपिंग सेवाएं 15 फरवरी, 2024 से जीजेईपीसी द्वारा नियंत्रित कर ली गई हैं।
- (ग) सुरक्षा सेवाएं 01 मार्च, 2024 से जीजेईपीसी द्वारा नियंत्रित ली जाएंगी।
- (घ) जीजेईपीसी द्वारा 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक मशीनरी और सभी बीएमएस सेवाओं का बीटा परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा।
- (ङ) वाणिज्यिक उत्पादन 01 अप्रैल, 2024 से शुरू होगा।
- (च) जीजेईपीसी 1 अप्रैल, 2024 से SEEPZ प्राधिकरण को किराया देना शुरू कर देगी।

घ) अनुसंशा:-

दिनांक 1.4.2024 से किराया भुगतान करने के लिए जीजेईपीसी के अनुरोध का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

यह कार्यसूची श्री घनश्याम भंडारीद्वारा तैयार की गई है।



**SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
MUMBAI

AGENDA ITEM NO. 07

A) Proposal:

Proposal for handing over of Ground to 5th floor of Mega CFC to GJEPC.

B) Relevant provision of SEZ Act, 2005 & Rules :

Section 34 of SEZ Act, 2005 and Rule 8 of SEZ Authority Rules 2009.

C) Other information:

This office vide letter dated 29.01.2024 informed the GJEPC that:

- (i) This office has received the Occupancy Certificate from the Special Planning Authority (MIDC) vide letter No. MIDC/DE&SPA/SEEPZ dated 08.01.2024 and the Final Fire NOC from the Chief Fire Officer, MIDC vide his letter No. I/34986/2024 dated 05.01.2024 and letter No. I/38010/2024 dated 25.01.2024 in respect of 1st Floor to 5th Floor of Mega CFC, SEEPZ-SEZ for occupation of the premises.
- (ii) In view of the above and as per the terms and conditions of MOU, 1st Floor to 5th Floor area of the Mega CFC were offered to GJEPC for operationalization and implementation of the project as approved in terms of LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/GJEPC/1/2023-24/14367 dated 03.10.2023 and requested to make all necessary arrangements for maintaining the said floors and ensure continued compliance of various statutory approvals.
- (iii) Further, with effect from 1st February, 2024, GJEPC will bear all the expenses towards maintenance cost of the area handed over to them including the rent to be paid to SEEPZ-SEZ Authority for the area handed over. The periodic compliance of Fire Department of MIDC, as per the floor wise Final Fire Approval dated 25.01.2024, is to be ensured at their end without any responsibility of SEEPZ SEZ Authority.
- (iv). Further, Basement, Ground Floor and 6th Floor was to be handed over to them after receipt of Final NOC from the Chief Fire Officer, MIDC as there were some changes in the initial plan of these floors based on inter alia requirements from GJEPC for optimum utilization of the space at the Ground Floor and 6th Floor.

In response to the letter dated 29.01.2024, GJEPC vide e-mail dated 21.02.2024 informed that:-

- (a) Fire NOC received on 15th Feb, 2024, accordingly they anticipate all factory licenses to be in place by 15th March, 2024.
- (b) Housekeeping Services are taken over by GJEPC from 15th Feb, 2024.
- (c) Security Services will be taken over by GJEPC from 01st March, 2024.
- (d) Beta Testing of Machinery & All BMS Services taken by GJEPC from 01st March, 2024 to 31st March, 2024.
- (e) Commercial Production to start from 01st April, 2024.
- (f) GJEPC will start paying rent to SEEPZ Authority from 1st April, 2024.

D) Recommendation:-

The proposal of the request of GJEPC to pay rent w.e.f. 1.4.2024 is submitted before the Authority for consideration.

Agenda Prepared by -Shri. Ghanashyam Bhandari (Asst.)



SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

ANDHERI (EAST), MUMBAI.

सुविधा प्रबंधन प्रभाग

FACILITY

MANAGEMENT Division

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीप्ल-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

कार्यसूची मद संख्या 08

प्रस्ताव :-

सीप्ल-सेज़ में व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना।

एसईजेड अधिनियम, २००५ और नियम, २००६/निर्देश/अधिसूचना के प्रासंगिक प्रावधान :-
धारा ३४ एसईजेड प्राधिकरण नियम २००९ के नियम ७ के साथ पठित।

अन्य सूचना :-

सीप्ल परिसर में एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों पर काम करने का निर्णय लिया गया। बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए आवश्यक अनुमानित लागत, ऐसे स्थापित संस्थानों से प्रदान की जा सकने वाली स्वास्थ्य सेवाएं आदि जैसे विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने के बाद, सीप्ल में व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र संस्थाओं/एजेंसियों से बोली लगाने का निमंत्रण मांगा जाता है। चयनित एजेंसी को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा और सीप्ल-सेज़ दिवस यानी ०१ .०५ .२०२४ को व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने की योजना है।

सिफ़ारिश :

सीप्ल-सेज़ में व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने का प्रस्ताव सूचना के लिए बोली मार्ग का पालन करके प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

यह कार्यसूची श्री जनेश त्रिपाठी (एलडीसी), श्री राजेश कुमार (यूडीसी), श्री मनीष कुमार (एडीसी) और डॉ. प्रसाद वरवंटकर (संपदा अधिकारी) द्वारा तैयार की गई है।

राजेश कुमार

जनेश त्रिपाठी

मनीष

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई

SEEPZ SEZ AUTHORITY
SEEPZ-SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
MUMBAI

कार्यसूची मद संख्या

AGENDA ITEM NO. 08

A. Proposal :-

Setting up an OHC (Occupational Health Clinic) in SEEPZ SEZ.

B. Relevant provisions of SEZ Act, 2005 & Rules, 2006/Instruction/ Notification:
Section 34 read with Rule 7 of SEZ Authority Rules 2009.

C. Other Information :-

It was decided to work on the feasibility and modalities for setting up a health unit in SEEPZ premises. After analyzing various factors such as estimated cost required for infrastructure and equipments, health services that can be provided from such established etc, an invitation to bid is called from the eligible entities/ agencies to provide support services for establishing an Occupational Health Clinic in SEEPZ. The selected agency will be on boarded on priority and it is planned to open the OHC on SEEPZ Day i.e. 01.05.2024.

D. Recommendation:

The proposal for setting up an OHC (Occupational Health Clinic) in SEEPZ SEZ is placed before authority by following the bidding route for information.

Agenda Prepared by – Shri. Janesh Tripathi (LDC), Shri. Rajesh Kumar (UDC), Shri. Manish Kumar (ADC) and Dr. Prasad Varvantkar (Estate Officer).



Janesh T.

